



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 19 सितम्बर, 1992/28 भाद्रपद, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 सितम्बर, 1992

संख्या 6-51/81-परि०-8.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सरकार की सम संख्यांक अधिसूचना तारीख 16 जून, 1992 द्वारा तारीख 16 जून, 1992 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में पूर्व प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश यात्री पथ परिवहन सेवा (उपांतरित) स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रसार.—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश यात्री पथ परिवहन सेवा (उपांतरित) (संशोधन) स्कीम, 1992 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

2. पैरा 2 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन सेवा (उपांतरित) स्कीम, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) में निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

2. हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम और प्राईवेट आपरेटरों सामान्य पथ परिवहन सेवा क्रमशः 70:30 अनुपात में निम्नलिखित के अनुसार भागीदारी करेंगे:—

- (1) 70:30 के अनुपात समस्त राज्य के लिए रखी जाएगी और इस अनुपात की परिगणना करने के लिए द्विपक्षीय करार के अधीन दूसरे राज्यों के पथ परिवहन उपक्रमों द्वारा हिमाचल प्रदेश में तय की गई दूरी, हिमाचल पथ परिवहन निगमों द्वारा तय की गई दूरी समझी जाएगी।
- (2) जहां पर प्राईवेट आपरेटरों को मिनी बस रूट परमिट के लिए आवेदकों की संख्या प्रदान किए जाने वाले परमिटों की संख्या से अधिक हो, निम्न क्रमानुसार अधिमान दिया जाएगा:—
  - (i) स्वतः नियोजित चालकों और संचालकों की सहकारिता सोसाइटी,
  - (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई परिवहन सहकारिता सोसाइटियां;
  - (iii) बेरोजगार व्यक्ति;
  - (iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से संबंधित व्यक्ति; और
  - (v) अन्य।
- (3) (i) जिलों में ग्रामों/नगरों का आपस में सरकारी मुख्यालयों, लोक सुविधाओं के स्थानों जैसे अस्पताल इत्यादि और व्यवसायिक धार्मिक तथा जिले के भीतर अन्य महत्व के केन्द्रों से जोड़ने के लिए मिनी बस परमिट प्राईवेट आपरेटरों को प्रदान किए जाएंगे;
- (ii) यात्रियों के अन्तर जिला परिवहन के लिए मिनी बस परमिटों की एक तरफ दूरी 50 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी;
- (iii) मिनी बस परमिट शहरी क्षेत्रों में यात्रियों के परिवहन के लिए भी प्रदान किए जा सकेंगे; और
- (iv) जहां पर प्राईवेट आपरेटरों को मिनी बस रूट परमिट के लिए आवेदकों की संख्या प्रदान किए जाने वाले परमिटों की संख्या से अधिक हो, निम्न क्रमानुसार अधिमान दिया जाएगा:—
  - (क) बेरोजगार व्यक्ति,
  - (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति, और
  - (ग) अन्य।
- (4) ड्राइवर और कंडक्टर के अतिरिक्त 6 से अधिक किन्तु 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित मोटर यानों के लिए शहरी क्षेत्र की सीमा में यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए स्टज वाहन परमिट प्रदान किए जाएंगे और शहरी क्षेत्र की सीमा से ग्रामीण क्षेत्र की दस किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए अनुज्ञा भी दी जा सकती है :

परन्तु जहां पर प्राईवेट आपरेटरों को रूट परमिट के लिए आवेदकों की संख्या प्रदान किए जाने वाले परमिटों की संख्या से अधिक हो, निम्न क्रमानुसार अधिमान दिया जाएगा:—

- (क) बेरोजगार व्यक्ति,
- (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित व्यक्ति; और
- (ग) अन्य।

3. पैरा 5 का संशोधन.—उपर्युक्त स्कीम को पैरा 5 का पैरा 3 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और ऐसे पुनःसंख्यांकित पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“3. ऐसे मोटर यानों द्वारा जिन्हें पैरा 2 के उप-पैरा (3) और उप-पैरा (4) के उपबन्धों के अधीन परमिट प्रदान किया गया है या किया जा सकेगा, तय की गई दूरी, हिमाचल पथ परिवहन निगम और

प्राइवेट आपरेटरों में 70:30 के अनुपात की भागीदारी के निर्धारण के लिए हिमाचल में नहीं ली जाएगी।”

4. पैरा 6 का संशोधन.—उपयुक्त स्कीम के पैरा 6 को पैरा 4 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“4. राज्य मुख्यालय को और राज्य मुख्यालय से अन्तर-राज्य रूट और लम्बी बहु जिला बस सेवा हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा अनमय रूप से परिचालित होती रहेगी :

परन्तु इन रूटों पर डीलक्स और अर्ध डिलक्स के लिए परमिट प्राइवेट परिचालकों को भी प्रदान किए जा सकेंगे।”

5. पैरा 5 का जोड़ा जाना.—ऐसे प्रतिस्थापित किए गए पैरा 4 के पश्चात निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थातः—

“5. प्राइवेट आपरेटरों को सभी परमिट सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित रूटों के लिए ही प्रदान किए जाएंगे।”

स्पष्टीकरण.— इस स्कीम के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति,—

(क) “कंडक्टर” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटरयान अधिनियम, 1988 के उपबन्धों के अधीन जारी विधिमान्य कंडक्टर अनुज्ञापति का धारक है, और जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम या निगम, जिसका स्वामित्व, नियन्त्रण या प्रबन्ध राज्य या केन्द्रीय सरकार के पास हो, की सेवा/नियोजन में न हो;

(ख) “ड्राइवर” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबन्धों के अधीन, मध्यम या भारी यानों को चलाने के लिए, विधिमान्य ड्राइवर अनुज्ञापति का धारक हो और जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम या निगम, जिसका स्वामित्व, नियन्त्रण या प्रबन्ध-राज्य या केन्द्रीय सरकार के पास हो, की सेवा नियोजन में न हो;

(ग) “मिनी बस” से ड्राइवर और कंडक्टर के अतिरिक्त बारह से अधिक किन्तु 30 से अनधिक यात्रियों का वहन करने के लिए निमित्त या अनुकूलित मोटर यान अभिप्रेत है;

(घ) “पथ परिवहन सेवा” से सड़क द्वारा किराए या परिश्रमिक के लिए यात्रियों या माल या दोनों का वहन करने के लिए मोटर यानों की सेवा अभिप्रेत है;

(ङ) “बेरोजगार” व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी प्राइवेट उपक्रम/स्थापन या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या निगम जिसका स्वामित्व, नियन्त्रण या प्रबन्ध राज्य या केन्द्रीय सरकार के पास हो, का पूर्ण कालिक वेतन भोगी कर्मचारी न हो और जिसका नाम हिमाचल प्रदेश द्वारा स्थापित या व्यवस्थित किसी रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत हो; और

(च) “शहरी क्षेत्र” से नगर निगम, नगरपालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्रशसित क्षेत्र अभिप्रेत है।

“(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस स्कीम में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके मोटर यान अधिनियम, 1988 में हैं।

6. उपाबन्ध का हटाया जाना.—उक्त स्कीम से संलग्न उपाबन्ध को हटा दिया जाएगा।

आदेश द्वारा,  
आर० के० आनन्द,  
वित्तियुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of the Government Notification No. 6-51/81-TPT-VIII, dated 8-9-92 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

## TRANSPORT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th September, 1992

**No. 6-51/81-TPT-VIII.**—In exercise of the powers conferred by section 102 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following Scheme, further to amend the Himachal Pradesh Passengers Road Transport Services (Modified) Scheme, 1991, after having been previously published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 16th June, 1992 *vide* Government Notification of even number dated 16th June, 1992, namely:—

1. *Short title and extent.*—(1) This scheme may be called the Himachal Pradesh Road Transport Services (Modified) (Amendment) Scheme, 1992.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

2. *Substitution of para 2.*—For para 2 of the Himachal Pradesh Passenger Road Transport Services (Modified) Scheme, 1991 (hereinafter called the said scheme) the following para shall be substituted, namely:—

“2. The Himachal Road Transport Corporation and private operators will share the ordinary road transport service in the ratio of 70:30 respectively in accordance with the following parameters:—

- (1) the ratio of 70:30 will be maintained for the State as a whole and to calculate this ratio distance covered in Himachal Pradesh by the Road Transport Undertakings of other States under bilateral agreement will be deemed to be the distance covered by the Himachal Road Transport Corporation;
- (2) where the number of applicants for route permits are more than the number of permits proposed to be granted to private operators, the preference will be given in the following order:—
  - (i) Co-operative Society of Self employed drivers and conductors;
  - (ii) transport co-operative societies registered or deemed to have been registered under any enactment for the time being in force;
  - (iii) unemployed persons;
  - (iv) persons belonging to scheduled castes and scheduled tribe; and
  - (v) others.

- (3) (i) Mini bus permit will be granted to private operators so as to inter-connect villages/towns with headquarters of Government offices, places of public amenities like hospitals etc. and centres of commercial, religious and other places of importance within a district;
- (ii) mini bus permit for inter district transportation of passenger shall not involve a route length of more than 50 kilometers one way;
- (iii) mini bus permit for transport of passengers within the urban areas may also be granted; and
- (iv) where the number of applicants for mini bus route permits are more than number of permits proposed to be granted to private operators, the preference will be given in the following orders:—
  - (a) unemployed persons;
  - (b) persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes; and
  - (c) others.
- (4) Stage carriage permit for motor vehicles constructed or adapted to carry more than six passengers but not more than twelve passengers excluding drivers and conductor will be granted for facilitating passenger movement within the limits of an urban area and can also be permitted to cover a distance of ten kilometers of rural area from the boundary of urban area:

Provided that where the number of applicants for route permits are more than the number of permits to be granted to private operators, the preference will be given in the following order:—

- (a) unemployed persons;
- (b) persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes; and
- (c) others."

3 *Amendment of para 5.*—Para 5 of the said scheme shall be renumbered as para 3 and for para 3 so renumbered the following shall be substituted, namely:—

- "3. Mileage covered by motor vehicles who have been or may be granted permits under the provisions of sub-para (3) and sub-para (4) of para 2 shall not be accounted for the determination of ratio 70:30 to be shared by Himachal Road Transport Corporation and private operators."

4. *Amendment of para 6.*—Para 6 of the said scheme shall be renumbered as para 4 and para 4 so renumbered the following shall be substituted namely :—

- "4. Inter State Routes and long multi-district bus services to and from State Head-quarter shall continue to be exclusively operated by the Himachal Road Transport Corporation:.

Provided that permits for delux and semi delux buses on these routs may also be granted to private operators.

5. *Addition of para 5.*—After para 4 so substituted, the following para shall be added, namely:—

“5, (1) All the permits to the private operators shall be granted only for the routes approved by the Government from time to time.

*Explanation.*—For the purposes of this scheme, the expressions,—

- (a) “conductor” means a person who holds valid conductor’s licence issued under the provisions of the Motor vehicles Act, 1988, and is not in service/employment in Central Government or State Government or in any Public Sector Undertakings or Corporation owned, controlled or managed by the State or Central Government ;
  - (b) “drived” means a person who holds a valid driving licence to drive medium or heavy vehicles issued under the provisions of the motor Vehicles Act, 1988, and is not in service/employment in Central Government or State Government or in any Public Sector Undertakings or Corporation owned, controlled or managed by the State or Central Government.
  - (c) “mini bus” means a motor vehicles constructed or adopted to carry more than twelve passengers but not more than 30 passengers excluding driver and conductor;
  - (d) “road Transport service” means a service of motor vehicles carrying passengers or goods or both by road for hire or reward ;
  - (e) “unemployed person” means a person who is not a whole time salaried employed or any State Government or Central Government or in any private undertaking/ establishment or public sector undertaking or corporation owned, controlled or managed by the State or Central Government and whose name is registered with any employment exchange established and maintained by the Government of Himachal Pradesh ; and
  - (f) “urban area” means any area administered by a Municipal Corporation, A Municipal Committee, a Cantonment Board, or a Notified Area Committee.”
2. The words are expressed used but not defined in this scheme shall have the same meanings as assigned to them in the Motor Vehicles Act, 1988.

6. *Deletion of Annexure.*—The Annexure appended to the said schemes shall be deleted.

By order,  
R. K. ANAND,  
Financial Commissioner-cum-Secretary.